‘राज्यसभा चुनाव को लेकर नैतिक रूप से हार मान चुके अशोक गहलोत’

विधायकों की जासूसी के लिए उनके घरों पर पुलिस का पहरा बिठा रखा है, पुलिस प्रशासन का जमकर दुरूपयोग किया जा रहाः डॉ. पूनिया

- **कांग्रेस के विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, खिलाफ बयान देते हैं तो यह उनके स्वयं के नेतृत्व की कमजोरी है, भाजपा पर झूठे आरोप मढ़ने से आप दोषमुक्त नहीं हो सकतेः डॉ. सतीश पूनिया।**
- **राजस्थान की जनता 2023 में जनविरोधी कांग्रेस सरकार को हमेशा के लिए नमस्कार कर हमेशा के लिये सत्ता से बाहर कर देगीः डॉ पूनिया।**

जयपुर, 7 जून (कासं)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक भ्रष्टाचार को लेकर तथा विकास कार्य नहीं होने इत्यादि को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं तो यह चिट्ठी कांग्रेस के विधायकों से भाजपा नहीं लिखवाती, आपकी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण कांग्रेस के विधायक ही सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं। उन्होंने कहा कि “हॉर्स ट्रेडिंग और एलीफैंट ट्रेडिंग की जनक कांग्रेस है, राजस्थान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जहां अशोक गहलोत ने अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए बसपा के विधायकों को बिना उनकी राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से कई बार मर्ज किया, क्या यह अलोकतांत्रिक व अनैतिक नहीं है?

उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस की सरकार को गिराने की कभी कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री की तानाशाही कार्यशैली से नाराज होकर उनके खुद के विधायक ही उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, खुद के विधायक ही नाराज होते हैं और इनके ही विधायक सरकार के मुखिया को चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी हठधर्मिता के कारण अपने विधायकों से मिलना भी पसंद नहीं करते। अब राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायक ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो क्या यह कांग्रेस के अंदर अंतरकलह और अंतर्विरोध नहीं है, क्या यह सब भाजपा करवा रही है?

पिछली बार राज्यसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम को पद से बर्खास्त किया और अपनी ही पार्टी के विधायकों पर राजद्रोह के केस लगवाए, क्या यह कांग्रेस के विधायकों की मुख्यमंत्री की मनमर्जी कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश नहीं था?

मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने से ज्यादा किसी बात की चिंता नहीं है, बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर जब मीडिया सवाल करता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं और नमस्कार कर चले जाते हैं, अब यही राजस्थान की जनता, बहन बेटियां, किसान और युवा 2023 में जनविरोधी कांग्रेस पार्टी कि सरकार को हमेशा के लिए नमस्कार कर सत्ता से बाहर करेंगे। कांग्रेस की सरकार डगमगा रही है और गिरने को तैयार है तो इसमें भाजपा का लेना देना नहीं है।

राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक

- **गायक सिद्धू मूसेवाला के घर जाते समय सही रूट की तलाश में राहुल गांधी का काफिला करीब 20 मिनट तक अनजान रूट पर भटकता रहा।**

नई दिल्ली, 7 जून। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने मंगलवार को राहुल गांधी मूसा पहुंचे। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला देखने को मिला है। उनका काफिला सही रूट की तलाश में करीब 20 मिनट तक भटकता रहा।

एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी का काफिला संगरूर रोड के बजाय अर्बन एस्टेट बाईपास रूट पर चला गया था। पटियाला पुलिस की सतर्कता से काफिले वापस सही रास्ते पर आया और फिर आगे बढ़ा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई मार्ग से पहुंचे थे। फिर आगे का रास्ता सड़क मार्ग के जरिए हुई।

राहुल गांधी अपने नेता मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए पंजाब पहुंचे थे।

तो क्या बीटीपी के समर्थन के लिए सरकार सामान्य वर्ग के खिलाफ फैसला लेने को तैयार है?

काकर डूंगरी मामले में दर्ज मुकदमों की फिर से जांच की बात करना इसी संकेत को दर्शा रहा है

- **बीटीपी की शर्त भी यही थी कि, पहले यह मुकदमे वापस लिए जाएं, फिर हम वोट देंगे।**
- **दूसरी ओर सरकार को अभी भी अपनों पर भरोसा नहीं, इसी के चलते परिवाद के बाद अब निर्वाचन अधिकारी को भी ज्ञापन दिया।**

उदयपुर, 7 जून (निसं)। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव काफी रोचक होता नजर आ रहा है। जहां सरकार पहले यह दावा कर रही थी कि 126 विधायक उनके साथ है। वही अब वह अपने विधायकों की खरीद-फरोख्त होने के डर से एसीबी में मामला दर्ज कराती है और सरकार की ओर से निर्वाचन अधिकारी को भी इस बाबत ज्ञापन दिया जाता है। यानी कि सरकार का या तो यह दावा गलत है या फिर सरकार को अपने ही खेमे पर विश्वास नहीं है।

दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने राज्यसभा चुनाव में बीटीपी के 2 विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए सोमवार देर रात को उसके दोनों विधायकों से उदयपुर के ताज अरावली में मुलाकात की। बताया जाता है कि बीटीपी विधायकों की सबसे प्रमुख मांग यही थी कि कांकर डूंगरी आंदोलन में जो 67 मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस लिया जाए। सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया है कि यह मुकदमे वापस लिए जाएंगे। हालांकि सरकार के ऐसा करने पर वागड़ क्षेत्र के अन्य वर्ग आगामी समय में कांग्रेस के खिलाफत में खड़े हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह लड़ाई सामान्य वर्ग तथा आदिवासियों के बीच भर्तियों को लेकर ही थी। इस आश्वासन के बावजूद बीटीपी के विधायक बाड़ेबंदी में नहीं रह कर बाहर ही रहेंगे।

देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बीटीपी के दोनों विधायकों से हुई बातचीत के बाद मंगलवार को होटल ताज अरावली के बाहर आकर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि अक्सर बड़ी घटनाओं में निर्दोष युवाओं पर भी मामले दर्ज हो जाते हैं, ऐसे में कांकर डूंगरी प्रकरण में दर्ज मुकदमों पर पुनर्विचार होगा।

‘यह कोई सीरियल बनाने जैसा काम नहीं, जहां सब कुछ खुद ही तय कर लेते हैं’

पायलट ने सुभाष चन्द्रा के बयान पर कटाक्ष किया

- **चन्द्रा ने कहा था कि, सचिन पायलट के पास यह मौका है, आज चूक गए तो 2028 तक सी.एम. नहीं बनेंगे।**
- **चन्द्रा का दावा-कांग्रेस के 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, अन्य पार्टियों के 4 विधायक मुझे वोट देंगे।**
- **चन्द्रा ने यह भी कहा कि, अशोक गहलोत भी मेरे मित्र हैं, मेरे प्रतिनिधि ने उनसे बात की थी।**

जयपुर, 7 जून (कासं)। राजस्थान के राज्यसभा चुनावों में भाजपा के समर्थन से निर्दलीय के रूप में राज्यसभा उम्मीदवार बनने वाले सुभाष चंद्रा ने कांग्रेस सहित अन्य वोट में सेंध लगाने का दावा करते हुए कहा कि 30 भाजपा विधायकों के अलावा कांग्रेस के 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। दूसरी पार्टियों के चार विधायक भी मुझे वोट करेंगे,तथा दो ऐसे विधायक हैं जो ना कांग्रेस को और ना भाजपा को वोट देंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक इसलिए क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि ये विधायक अपने ही राज में परेशान हो रहे हैं। एक तरह से जलालत महसूस कर रहे हैं।

सुभाष चंद्रा ने कहा कि सचिन पायलट के पास यह मौका है, आज यह मौका चूक गए तो 2028 तक सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि पायलट कांग्रेस के जुझारू नेता हैं। उनके पिता से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। चंद्रा के इस दावे पर सचिन पायलट ने भी जवाब देते हुए कहा कि 10 तारीख को वोटिंग से पहले अच्छा है कि भाजपा के समर्थन से निर्दलीय आने वाले विनम्रता से अलग हो जाएं,क्योंकि यह काम टीवी सीरियल बनाने जैसा नहीं है, जहां सब कुछ आप ही तय करते हैं।

दूसरी ओर चंद्रा ने यह भी कहा कि जिस तरह से अशोक गहलोत हाईकमान को आंख दिखाते हैं, उसी तरह सचिन पायलट को भी अब स्टैंड लेना चाहिए। राज्यसभा चुनावों में उनके पास मौका है, अगर वे समर्थन करते हैं तो 2023 में उनके सीएम बनने के चांस बनते हैं, नहीं तो 2028 तक कोई चांस नहीं है। सुभाष चंद्रा ने कहा कि कल तक गाली देने वाले विधायक अचानक सीएम के प्लेन में कैसे आ गए, मैने चुनाव आयोग को इस बारे में शिकायती पत्र दिया है।

कस्टम विभाग 42 हजार किलो ड्रग्स नष्ट करेगा

- **देश के विभिन्न स्थानों से बीते एक साल में इतनी बड़ी संख्या में यह ड्रग्स बरामद हुई है।**

नई दिल्ली, 7 जून (वार्ता)। वित्त मंत्रालय की एजेंसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) बुधवार को लखनऊ,पटना और मुंबई समेत देश भर में 14 जगह कुल करीब 42,000 किलोग्राम मादक द्रव्य नष्ट करेगी।

वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार सी.बी.आई.सी. वित्त मंत्रालय के विशिष्ट सप्ताह के कार्यक्रमों के सिलसिले में कल मादक औषधि विध्वंस दिवस का आयोजन किया है। इसके तहत देश भर में 14 जगहों पर 42 हजार किलोग्राम के करीब जब्त मादक द्रव्यों को नष्ट किया जाएगा।

विज्ञप्ति के अनुसार लखनऊ, मुंबई, मुंद्रा/कांडला, पटना और सिलीगुड़ी में मादक द्रव्य नष्ट करने की कार्रवाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिजिटल माध्यम से देखेंगी।

चीफ ऑफ डिफैन्स स्टाफ के चयन के दायरे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रूप से प्रभावित होगा तथा पदस्थ उच्च पदाधिकारियों को या तो ससम्मान समायोजित किया जायेगा या फिर उन्हें पद त्याग करना होगा। थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना जैसे उच्च स्तरों वाली संरचना में इस प्रकार के गतिरोध तनाव जन्य एवं संकटपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं।

सेनाओं के सर्वोच्च पदों के क्षेत्र में पार्श्व से प्रवेश करते समय सरकार को बहुत अधिक सावधानी एवं सतर्कता बरतनी होगी। ऐसे कदमों से सर्वोच्च अधिकारियों का मनोबल प्रभावित नहीं होना चाहिये तथा उनमें तनाव एवं मनमुटाव जैसी भावनाएं पैदा नहीं होनी चाहिये। ऐसे अतिवादी सुधार लाने से पहले, वैकल्पिक समायोजन तथा पदों के ढ़ाँचे या स्तरों पर गहन विचार किया जाना परमावश्यक है।

इसके साथ ही, संकटकालीन स्थितियों के लिये असाधारण प्रतिभाओं के चयन की आवश्यकता को भी कम करके नहीं आँका जा सकता। विभिन्न दिशाओं, जैसे चीन की ओर से हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मिल रही चुनौतियों के चलते, सेनाओं के व्यवस्थापन में मौलिक एवं अभिनव सोच की जरूरत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।

इन दिनों, सेना एवं सुरक्षा अधिक से अधिक विज्ञान-आधारित एवं विज्ञान-केन्द्रित होती जा रही हैं। नया हथियार-तंत्र विकसित हो रहा है, जो नवीनतम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अत्यधिक दक्ष एवं कुशल टैक्नोक्रेट उस हथियार तंत्र को बहुत दूर बैठकर संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। चीन, जो हमारा सबसे बड़ा सैन्य खतरा है, इस प्रकार के नये हथियार एवं क्षमताएं विकसित करने में लगा हुआ है।

चीन द्वारा प्रदर्शित उसकी नवीनतम एवं आधुनिक क्षमता के अन्तर्गत, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तैनात किये जा रहे हैं, जिनकी गति, ध्वनि से भी ज्यादा तेज है तथा इतनी नीचाई पर उड़ते हैं कि राडारों की पकड़ में भी नहीं आ सकते लेजर-बेस्ड गाइडेड मिसाइलें तथा व्हीकल अब हमले करने एवं बचाव करने के काम भी लिये जा रहे हैं।

शक्तिशाली टैंकों को ध्वस्त करने में ड्रोन्स की उपयोगिता यूक्रेन युद्ध में दिखाई दे रही हे। इस युद्ध में ड्रोन्स को काम मे ले रहे यूक्रेनियन सेनाओं ने रूस के करीब एक हजार टैंक नष्ट कर दिये हैं।

गुप्तचर-व्यवस्था एक और ऐसा हथियार है। जिसका उपयोग चमत्कारिक सफलताओं के लिये किया जा रहाहै। रूस की ब्लैक सी कमान के फ्लैगशिप के बारे में अमेरिकन जासूसी के कारण ही, यूक्रेन ने केवल दो मिसाइले दाग कर ही फ्लैगशिप को डुबो दिया था। आधुनिक युद्ध कला, सेना एवं सुरक्षा मामलों में, सैन्य प्रमुख इतना सर्मा होना चाहिये कि वह इन तीनों प्रकार की सेनाओं से परे, अन्य साधनों से आने वाली चुनौतियों पर विचार कर सके तथा संयुक्त सैन्य पड़ाव डाल सके, जनमें तीनों सेनाओं को काम में लेने के अलावा, तकनीक आधारित युद्ध कला युक्त कुछ और भी फलदायी संकट शत्रु के सामने खड़े किये जा सकें।

हमारे सैन्य ढ़ाँचों में इस प्रकार की बहुआयामी क्षमताओं को काम में लेने में युवा मस्तिष्क ज्यादा उपयुक्त एवं निपुण हो सकते हैं। नये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करने के अलावा, सरकार के लिये यह भी जरूरी है कि वह विज्ञान-आधारित सैन्य सेवा की एक पृथक शखा स्थापित करे।

इस सेवा के लिये कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भर्ती किये जाने चाहिये तथा उन्हें रक्षा-सुरक्षा की तकनीकें विकसित करने के नये-नये तरीकों के आँकलन एवं सुझाव देने पर, सैन्य सेवाओं के इन-हाउस स्टाफ के साथ चर्चा करते रहना चाहिये। समय बदल रहा है तथा सेना को समय के साथ कदम मिलाते हुये चलना होगा।

आज सेना का काम केवल बाहुबल तक सीमित नहीं है। अब शारीरिक ताकत के साथ दिमागी ताकत भी जयरी है।

कांग्रेस को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाली सड़क पर निर्मित इस मुख्यालय में नहीं जाना चाहती। कांग्रेस के इस भवन के दो मुख्य द्वार हैं, जिनमें से एक दीनदयाल मार्ग तथा दूसरा कोटला रोड पर खुलता है। कांग्रेस चाहती है कि इस भवन का पता बदलकर 2, कोटला रोड कर दिया जाये। लेकिन अधिकारीगण कोटला रोड पर मुख्य द्वार रखे जाने के विरूद्ध हैं। यह नया भवन, जिसे फिलहाल इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता हैं, में इस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है। पार्टी पहले तो यह चाहती थी कि उसका मुख्यालय संसद के नज़दीक हो तथा इसलिये राजीव गांधी ने 1984 में सरकार से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग पर भूमि आवंटित करा ली थी। उस जगह एक आधुनिक किस्म का भवन, जिसे जवाहर भवन नाम दिया गया था, बनवा लिया था, लेकिन पार्टी मुख्यालय के रूप में इस भवन को खारिज कर दिया क्योंकि इसका अग्र भाग कांच का होने के कारण, यह नेताओं के लिये असुरक्षित था। इस समय यह भवन राजीव गांधी फाउण्डेशन का मुख्यालय है। जवाहर भवन के पीछे, बँगला नं. 5, रायसीना रोड, इंडियन यूथ कांग्रेस तथा नैशनल स्टुडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एन.एस.यू.आई.), जो कांग्रेस की विद्यार्थी शाखा है, का मुख्यालय है। सरकार इसे खाली करने के लिये अनेक नोटिस भेज चुकी है। इसके अलावा, कांग्रेस का एक कार्यालय 15, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर भी है। यह भी सरकारी बँगला है, जो कांग्रेस का वॉर रूम है तथा इसका उपयोग रणनीतिक मीटिंगों के लिये होता है।

मस्कट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसके पति का पासपोर्ट कंपनी ने जब्त कर लिया है जो कि ओमान ट्रेडिंग कंपनी में ब्रांच मैनेजर थे। कंपनी हुंडई की वितरक है। उसके पति का पासपोर्ट गैर कानूनी तरीके से तब जब्त कर लिया गया जब उन्होंने अपने मातहत कार्यरत ओमानी स्टाफ को निकाल दिया था।

मीना ने अपनी अपील में कहा उसके पति व उसके परिवार को खतरा है इसलिए उसने अपने 13 साल के बेटे और 7 साल की बेटी को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया है।

उसने लिखा है कि हम डर में जी रहे है। उसने कहा कि वह तकनीकी रूप से भारत लौट सकती है पर वह अपने पति की सुरक्षा के लिए वहीं रूकना चाहती है। क्योंकि वे पहले से ही भारी अवसाद में है।

वैसे यह नई बात नहीं है खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे भारतीयों से वहां की कम्पनियां पासपोर्ट जमा करवाने के लिए कहती है और फिर अगर वे नौकरी छोड़ना चाहें या बदलना चाहें तो उन्हें परेशान करती हैं।

‘सत्येंद्र जैन के परिसरों से 2.85 करोड़ कैश व 1.8 किलो सोना बरामद हुआ’

ई.डी. ने सत्येंद्र जैन एवं उनके करीबी दोस्तों के परिसरों पर छापेमारी के बाद यह वक्तव्य दिया

- **दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को ई.डी. ने मनी लॉण्डरिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और वे इस समय ई.डी. की हिरासत में हैं। उन्हें निचली अदालत ने 31 मई को नौ जून तक के लिए ई.डी. की हिरासत में भेजा है।**

नई दिल्ली, 7 जून (वार्ता)। प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने मंगलवार को बताया कि उसने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य के ठिकानों पर छापे डालकर 2.85 करोड़ रुपये नगद, 1.80 किलोग्राम वजन के सोने के कुल 133 सिक्के और दस्तावेज तथा डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए हैं।

ई.डी. ने एक बयान में कहा कि छापे की यह कार्रवाई सोमवार को की गयी। इसमें नगदी और सोने के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। ई.डी. ने कहा है कि जब्त नगदी और सोने के स्रोत की जानकारी उसे नहीं दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि सत्येंद्र जैन को 30 मई को एजेंसी ने धन शोधन निवारक अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और वह इस समय ई.डी. की हिरासत में हैं। उन्हें निचली अदालत ने 31 मई को नौ जून तक के लिए ई.डी. की हिरासत में भेजा है। ई.डी. ने कहा है कि इस कार्रवाई में सत्येंद्र जैन/पूनम जैन और उन्हें धन शोधन की कार्रवाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाले या उसमें भाग लेने वाले अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (मेसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स प्रा. लि. के निदेशक), जी.एस. मथरू (प्रूडेंस स्कूल चलाने वाले लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के चेयरमैन), योगेश कुमार जैन (निदेशक/ राम प्रकाश ज्वैलर्स प्रा. लि.), मेसर्स लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के ठिकानों पर तलाशी ली गयी। ई.डी. ने कहा है कि जांच में पता चला है कि मेसर्स लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के एक व्यक्ति ने सत्येंद्र जैन की कंपनी से उनके साथियों को जमीनों के हस्तांतरण के लिए दिखावे के सौदों की प्रविष्टियां दर्ज कीं।

‘हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो नाम से शिकायत दर्ज करानी चाहिए’

पायलट कैम्प के विधायक ने महेश जोशी पर कटाक्ष किया

- **“खरीद-फरोख्त का दावा है तो शिकायत में नाम लिखना चाहिए, ताकि पता लग सके कि कौन ऐसा कर रहा है।”**

जयपुर, 7 जून (कासं)। राजस्थान में हो रहे 4 सीटों के राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने सभी विधायकों को उदयपुर के ताज अरावली की बॉड़ेबंदी में पहुंचाने में लगी है और कुछ बीमार विधायकों सहित चार पांच मंत्रियों के अलावा सभी विधायक उदयपुर पहुंच भी चुके हैं। सरकार अपने पास 126 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है लेकिन राजस्थान के सरकारी मुख्य सचेतक ने पहले एसीबी में खरीद-फरोख्त को लेकर परिवाद दायर किया तो अब निर्वाचन अधिकारी को भी शिकायत दी है। इन परिवाद और शिकायतों को लेकर सचिन पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने सवाल किया है कि आखिरकार कौन खरीद-फरोख्त कर रहा है इस बारे में नाम भी बताया जाना चाहिए।

सोलंकी ने कहा कि में बीते 7 दिन से घर पर हूं, मुझसे न किसी ने संपर्क किया और न ही किसी तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास हो रहा है। अगर किसी को शिकायत दर्ज करानी हो तो उसे नाम के साथ शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, ताकि कम से कम किस की शिकायत हो रही है कि किसके ऊपर शक है उसकी जांच तो हो सके।

राज्यसभा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रही है और उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना नजर आती है। आयोग से कालेधन के उपयोग को रोकने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस की ओर से राज्य के जलदाय मंत्री एवं सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शिकायत दी है, जबकि भाजपा की ओर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता राजेन्द्र राठौड़ और प्रतिपक्ष के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने शिकायत दर्ज करवाई है।

‘91 के “प्लेसेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहिए। याचिकाकर्ता काबोत्रा ने कहा कि केन्द्र ने कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन के उपाय का अपनी विधायी शक्तियों से अतिक्रमण किया है जो कि संविधान की आधारभूत विशेषता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया हिंदू, जैन, बौद्धो और सिखों को पहुंचाई गई चोट बहुत बड़ी है और 1991 अधिनियम के सैक्शन्स 2, 3, और 4 ने कोर्ट के पास जाने का अधिकार छीन लिया और इस प्रकार न्यायिक समाधान का अधिकार खत्म हो गया है।

याचिका के अनुसार केन्द्र नाराज हिंदुओं, जैन, बौद्धों और सिखों के लिए अपैलेट कोर्ट्स, संवैधानिक अदालतों का दरवाजा बंद नहीं कर सकता ना ही हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 226 और 32 के तहत दी गई शक्तियां छीन सकता है। इसने दावा किया कि एक्ट ने हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के धर्म स्थलो पर अतिक्रमण के खिलाफ न्याय पाने के अधिकार को यह एक्ट बाधित करता है।

याचिका में एक्ट के सैक्शन 2,3, 4 को रद्द करने और असंवैधानिक करार देने की अपील की है क्योंकि यह समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता व अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है और प्राचीन और एतिहासिक पूजा स्थलों पर विदेशी हमलावरों के कब्जे को वैध ठहराता है। इसने कहा कि कानून का क्रियान्वयन करते हुए केन्द्र ने भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को इससे अलग रखा था पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को नहीं, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है।

‘औरंगज़ेब की सेना अकबर की सेना से काफी ज्यादा विशाल थी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **उनका कहना था, जिन हिन्दू कानूनों व फिलॉसफी की सदियों से विवेचना होती आयी है तथा स्थापित है, उनका आधुनिक सोच के अनुसार विश्लेषण करना सही नहीं है।**
- **सैय्यद अहमद इलाहाबाद के आनंद भवन के प्रथम मालिक थे तथा बाद में यह बंगला 1900 में मोतीलाल नेहरू ने मुरादाबाद के राजा परमानंद से खरीदा था।**

विवेक की झलक उनके द्वारा किए गए मुगल साम्राज्य के आकलन से मिलती है। अकबर और औरंगज़ेब ने साम्राज्यों की तुलना करते हुए वे कहते हैं कि “ऐसा क्या था जिसने अकबर के शासन को इतना शानदार और समृद्ध बना दिया, जबकि उसकी सेना की संख्या औरंगज़ेब की सेना की संख्या से कम थी।” वह एक सवाल खड़ा करते हैं और बाद में उसका उत्तर देते हैं कि “औरगज़ेब ने नैतिक कारकों की पूर्णतः उपेक्षा की। उसने अपनी प्रजा की भावनाओं की परवाह नहीं की।”

महमूद के आकलन में औरंगज़ेब एक बड़े राजनेता थे। उनकी राज-कार्य पद्धति सैन्य अनुशासन और शारीरिक शक्ति की सफलता पर निर्भर थी। वह “सौहार्दपूर्ण तरीकों” की क्षमता को तवज्जो देने में विफल रहे, जिन पर उनके पूर्वजों का भरोसा था। खासतौर पर अकबर ने अपने प्रशासन में यही रीति अपनाई थी।

सर सैयद अहमद के पुत्र महमूद ने अपने 53 वर्ष के लघु जीवन में ना केवल अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और लैटिन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज से डिग्री लेन के बाद बैरिस्टर बनने के लिए कानून की शिक्षा भी पूर्ण थी। वर्ष 1879 में जब उन्होंने भारतीय सिविल सेवा में कार्यभार ग्रहण किया, उससे पहले ही वह इण्डियन एविडैन्स एक्ट पर एक कमैन्ट्री लिख चुके थे और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएन्टल (एम.ए.ओ.) कॉलेज की नींव डाल चुके थे जो बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना।

और 19वीं शताब्दी में महमूद शायद ऐसे पहले जज बने जिन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता का समर्थन कर औपनिवेशी शक्तियों का विरोध किया। पुस्तक के लेखक वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद मची उथल-पुथल के समय के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जिक्र करते हुए उल्लेख करते हैं कि यह एक बदला हुआ भारत था, जिसकी मनोदशा में प्रबल बदलाव की जरूरत थी क्योंकि इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश हुकूमत स्वयं को स्वीकार बनाने और विश्वास बहाल करवाने के प्रयत्न कर रही थी।

पुस्तक में कहा गया है कि वह हाई कोर्ट में सिर्फ एक अस्थायी न्यायाधीश थे, लेकिन उन्होंने बड़े जोश और निर्भीकता से विरोधी प्रकृति के निर्णय लिखे क्योंकि वह ऐसे जज थे जिनमें ब्रिटिश जजों की तुलना में ज्यादा बुद्धि थी। औपनिवेशिक भारत के एक भारतीय जज के रूप में उन्हें कभी-कभी दोहरा अन्तःकरण रखते हुए मिसाल देनी पड़ती थी और ब्रिटिश इण्डिया में एक भारतीय जज के रूप में सोचना पड़ता था। अतः उन पर आए अधिक सोच के दबाव को कोई समझ सकता है। 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही के दिनों में महमूद के बारे में सोचा जाए तो यह वह समय था साम्राज्यवादी व्यवस्था में अधीनता को एक महज अंदाज में लिया जाता था।

हाईकोर्ट जज के अपने छह वर्ष के छोटे कार्यकाल और वर्ष के न्यायिक करियर में वह प्राचीन हिंदू व मुस्लिम विधियों तथा इंग्लैण्ड के विधान से सीधे लिए गए सामान्य कानूनों में एकरुपता का सूत्रपात कर सकते थे। ये विधियां मूलपाठों में आ गई हैं और उनके द्वारा दिए गए कई निर्णय देश के न्यायिक इतिहास व व्यवहार में बने हैं। यहां तक कि उनके विरोधी निर्णयों को भी विश्वभर के समकालीन अधिनियमों और विधियों में मौलिक माना जाता है।

पेशेवर उपलब्धियों के अलावा उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था और वह न्यायिक स्वतंत्रता के स्तंभों को खड़ा करने, शिक्षा के जरिए सशक्तीकरण करने और उस सहिष्णुता के लिए दृढ़ रहकर आधारभूत कार्य करते रहे जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान “भारत के विचार” के रूप में विकसित हुई और बाद में संविधान में प्रतिष्ठापित हुई।

बायोग्राफी में जो अन्य मजेदार तथ्य प्रकाश में आया है वह है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के आलीशान आवास “स्वराज भवन” था, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम की कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का गवाह रहा है। यह आवास मूल रूप से जस्टिस महमूद का था। उन्होंने इलाहबाद हाई कोर्ट से इस्तीफ देने के बाद इसे मुरादाबाद के राजा प्रेमानंद को बेच दिया था और उनसे मोतीलाल नेहरू ने इसे वर्ष 1900 में खरीद लिया था।

लेखकों ने उनके जीवन वृत्त और उपलब्धियों को वर्तमान पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत कर सराहनीय कार्य किया है, अन्यथा वह अपने पूर्वजों की उपलब्धियों से बेखबर रह जाती, लेकिन इसके साथ ही दोनों लेखक महमूद की कमजोरियों पर चूक या अनदेखी ना करने के प्रति भी सावचेत रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वह शराब के आदी थे और संभवतः इसी वजह से उनका शानदार जीवन समय पूर्व ही समाप्त हो गया।

सोनिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) के समक्ष अपने खराब स्वास्थ्य के कारण प्रस्तुत नहीं हो पाएंगी। इसलिए उन्होंने दूसरी तारीख मांगी है। पार्टी सूत्रों ने कहा, वो वायरल इन्फैक्शन से मुक्त नहीं हुई हैं और टैस्ट में कोविड-19 के लिए अभी नैगेटिव आना बाकी है। ई.डी. ने उन्हें दिल्ली के अपने मुख्यालय पर प्रस्तुत होने के लिए कहा था।

सोनिया गांधी के साथ, 2 जून को उनके पुत्र राहुल को भी ई.डी.के समक्ष प्रस्तुत होने का सम्मन दिया गया था। राहुल की इस प्रार्थना पर कि, 5 जून तक वो विदेश में हैं, ई.डी. ने उन्हें 13 जून को ई.डी. के समक्ष प्रस्तुत होने के नए सम्मन जारी किए थे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908